Daily Current Affairs

Date : 02 July, 2026

UTKARSH CLASSES CIVIL SERVICES

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में स्टार्ट-अप्स और इनोवेशन की स्थिति
2.	राजस्थान का पहला 'AI-Ready' डेटा सेंटर : जयपुर
3.	'लोकमंथन' के पाँचवें संस्करण का आयोजन राजस्थान में
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राज्य व्यापी विशेष हेलमेट जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान 2. "प्रेरणा पखवाड़ा" : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयन्ती के उपलक्ष्य में शुरुआत 3. 'खिलौना बैंक', 'प्रवेशोत्सव एवं वृक्षारोपण' कार्यक्रम 4. 'GST पंजीकरण और ऑडिट' के क्षेत्र में जयपुर देश भर में प्रथम स्थान पर 5. लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा
5.	जनरल धीरज सेठ ने सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया।
6.	ई-ओसीआई कार्ड
7.	अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)
8.	किसान सारथी प्लेटफ़ॉर्म
9.	सारस शक्ति
10.	डिजिटल इंडिया
11.	पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट

राजस्थान परिदृश्य

राजस्थान में स्टार्ट-अप्स और इनोवेशन की स्थिति

चर्चा में क्यों?

- स्टार्ट-अप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहाँ विगत दो वर्षों में स्टार्टअप्स की संख्या 4,000 से बढ़कर 8500 से अधिक हो गई है। (स्रोत - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान)

मुख्य बिन्दु:

- **निवेश और रोजगार :** राज्य में स्टार्ट-अप्स में निवेश ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹1,000 करोड़ हो गया है, वहीं रोजगार सृजन का आँकड़ा 22,000 से बढ़कर 47,000 से अधिक हो गया है।
- **इन्क्यूबेशन सेंटर और लॉन्चपैड :** राज्य सरकार ने प्रदेश में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए 9 इन्क्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्चपैड स्थापित किए हैं।
- ग्रामीण एवं विद्यालयी स्तर पर डिजिटल ढाँचा सशक्त करने के उद्देश्य से 65 आई-स्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित कर 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा गया है।

प्रमुख नीतियाँ और मिशन:

- **राजस्थान AI-ML पॉलिसी - 2026 :** इसके माध्यम से AI के उपयोग से प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्यों का आधार तैयार हुआ है।
- **राजस्थान AVGC-XR नीति :** सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 'एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एण्ड एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) पॉलिसी – 2024' लॉन्च की गई है।
- **राजस्थान AI एवं क्वांटम कम्प्यूटिंग मिशन :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) को शिक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों में प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से।

- **'एडवांस क्वांटम' और 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' प्रयोगशालाएँ :** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT), जयपुर' में स्थापित की जाएंगी।
- **iStart राजस्थान :** यह राजस्थान सरकार का एक प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार कार्यक्रम है। इसका संचालन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना, नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- **राजस्थान स्टार्टअप फंड :** राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमियों और नवोन्मेषी व्यवसायों के लिए ₹100 करोड़ का 'राजस्थान स्टार्टअप फंड' (फंड ऑफ फंड्स) स्थापित किया है।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

Q1. 'iStart राजस्थान' कार्यक्रम का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है?

(A) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

(B) उच्च शिक्षा विभाग

(C) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

(D) कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग

Q2. 'राजस्थान में स्टार्ट-अप्स और इनोवेशन' के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है?

(A) प्रदेश में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए 9 इन्क्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्चपैड स्थापित किए हैं।

(B) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT), जयपुर' में स्थापित की जाएंगी।

(C) राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमियों और नवोन्मेषी व्यवसायों के लिए ₹50 करोड़ का 'राजस्थान स्टार्टअप फंड' (फंड ऑफ फंड्स) स्थापित किया है।

(D) iStart राजस्थान का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा किया जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान का पहला 'AI-Ready' डेटा सेंटर : जयपुर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, ST टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स (STT GDC) इंडिया द्वारा जयपुर में राजस्थान का पहला AI-Ready डेटा सेंटर स्थापित किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **सेंटर का नाम :** STT Jaipur-1
- उल्लेखनीय है कि ST टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स (STT GDC) इंडिया देश की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कोलोकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है।
- नव-स्थापित एडवांस्ड और एंटरप्राइज-ग्रेड डेटा सेंटर विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- जून, 2026 तक राजस्थान में डेटा सेंटर क्षेत्र में (स्थापना, संचालन और रखरखाव) ₹43,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान AI-ML पॉलिसी – 2026:

- **लॉन्च :** मुख्यमंत्री द्वारा 06 जनवरी, 2026 को जयपुर में 'राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस – 2026' के दौरान।
- **पूरा नाम :** राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड मशीन लर्निंग (AI-ML) पॉलिसी - 2026
- **घोषणा :** इस नीति की घोषणा राजस्थान बजट 2025-26 में की गई थी।
- **अनुमोदन :** राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 30 दिसंबर, 2025 को अनुमोदन किया गया।
- **उद्देश्य :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना तथा नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- साथ ही, राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITES) के हब के रूप में विकसित करना इस नीति के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है।
- यह पॉलिसी सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ई-गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करेगी।
- **प्रावधान :** इस नीति के अंतर्गत AI सिस्टम्स पारदर्शी, जवाबदेह, निष्पक्ष, गोपनीयता-संरक्षित बनाने के साथ-साथ AI प्रणालियों में पक्षपात को कम करने, डेटा की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष बल दिया गया है।
- नीति में AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रियाओं का प्रावधान भी किया गया है।

- इस नीति में स्कूलों, ITIs, पॉलिटेक्निक संस्थानों और कॉलेजों में AI शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है।
- नोट : नीति में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना किए जाने का प्रावधान है।
- नीति के तहत प्रत्येक विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में AI उपयोग की संभावनाओं की पहचान करेगा तथा एक AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. हाल ही में राजस्थान का पहला AI-Ready डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है?

(A) जोधपुर

(B) उदयपुर

(C) जयपुर

(D) कोटा

Q2. राजस्थान AI-ML पॉलिसी–2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. इस नीति को मुख्यमंत्री द्वारा 06 जनवरी, 2026 को जयपुर में लॉन्च किया गया।
2. इस नीति की घोषणा राजस्थान बजट 2025-26 में की गई थी।
3. इस नीति का अनुमोदन राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 30 दिसंबर, 2025 को किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

‘लोकमंथन’ के पाँचवें संस्करण का आयोजन राजस्थान में

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में ‘लोकमंथन-2026’ का कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- इस अवसर पर लोकमंथन की वेबसाइट का लोकार्पण और प्रज्ञा प्रवाह समिति के संयोजक जे. नंद कुमार द्वारा लिखित पुस्तक ‘फोक से परे लोक’ का विमोचन किया गया।
- 'लोकमंथन' के पाँचवें संस्करण का आयोजन जयपुर में दिसंबर, 2026 में होगा।
- वर्ष 2026 का विषय : ‘हम भारत के लोग’।
- भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय चिंतन के इस मंच का पहला संस्करण वर्ष 2016 में भोपाल में हुआ था।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. ‘लोकमंथन’ के पाँचवें संस्करण का आयोजन कहाँ और कब होगा?

(A) भोपाल, दिसंबर 2026

(B) जयपुर, दिसंबर 2026

(C) वाराणसी, नवंबर 2026

(D) नई दिल्ली, जनवरी 2027

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**राज्य व्यापी विशेष हेलमेट जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान** ■ **आयोजन :** 2 से 16 जुलाई, 2026 तक। ■ **आयोजक :** राजस्थान पुलिस। ■ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 'राज्य सड़क सुरक्षा रणनीति एवं कार्ययोजना' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2030 तक राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मृत्युदर को चरणबद्ध तरीके से 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2.	**"प्रेरणा पखवाड़ा" : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयन्ती के उपलक्ष्य में शुरुआत** ■ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयन्ती के उपलक्ष्य में 1 से 14 जुलाई, 2026 तक "प्रेरणा पखवाड़ा" का आयोजन किया जा रहा है। ■ राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित इस विशेष पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य युवाओं को डॉ. मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवाद और विचारों से प्रेरित करना है। ■ उल्लेखनीय है कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मुखर्जी के आदर्शों से आम भारतीय को अवगत करवाने हेतु 2 वर्षीय स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
3.	**'खिलौना बैंक', 'प्रवेशोत्सव एवं वृक्षारोपण' कार्यक्रम** ■ 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ICDS निदेशालय द्वारा 01 जुलाई, 2026 को प्रदेशभर के आँगनबाड़ी केंद्रों पर 'खिलौना बैंक', 'प्रवेशोत्सव एवं वृक्षारोपण' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ■ उल्लेखनीय है कि अभियान के तहत प्रदेश के सभी आँगनबाड़ी केंद्रों पर 'खिलौना बैंक' स्थापित किए गए हैं।

4.	**'GST पंजीकरण और ऑडिट' के क्षेत्र में जयपुर देश भर में प्रथम स्थान पर** ■ **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) लेखापरीक्षा आयुक्त, जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखापरीक्षा प्रदर्शन सूचकांक (API) मूल्यांकन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।** ■ **यह मूल्यांकन वर्ष 2021 के दौरान किए गए लेखापरीक्षा कार्यों पर आधारित था और इसमें लेखापरीक्षा की गुणवत्ता, समीक्षा मानकों और समग्र प्रदर्शन का आकलन किया गया।** ■ **अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क मुख्यालय, नई दिल्ली के अंतर्गत लेखापरीक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी परिणामों के अंतर्गत CGST जयपुर ने 100 में से 83.66 अंक प्राप्त किए।**
5.	**लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा** ■ **लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा (AVSM, SM) ने 1 जुलाई, 2026 को भारतीय सेना की जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमान (सप्त शक्ति कमान) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।** ■ **उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मंजींदर सिंह का स्थान लिया।**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q1. "प्रेरणा पखवाड़ा" का आयोजन किसकी 125वीं जन्म जयन्ती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है?

(A) पंडित दीनदयाल उपाध्याय

(B) सरदार वल्लभभाई पटेल

(C) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

(D) अटल बिहारी वाजपेयी

Q2. 1 जुलाई, 2026 को दक्षिण-पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया?

(A) लेफ्टिनेंट जनरल मंजींदर सिंह

(B) लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा

(C) लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी

(D) लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता

राष्ट्रीय परिदृश्य

जनरल धीरज सेठ ने सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया।

चर्चा में क्यों?

- जनरल धीरज सेठ ने औपचारिक रूप से भारतीय सेना के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

मुख्य बिन्दु:

- उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है, जो 40 से अधिक वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।

जनरल धीरज सेठ

- जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, भारतीय सेना के एक उच्च कोटि के सम्मानित चार सितारा जनरल अधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में विशिष्ट बख्तरबंद कोर (विशेष रूप से द्वितीय लांसर्स/गार्डनर्स हॉर्स) में कमीशन प्राप्त करने वाले धीरज सेठ लगभग चार दशकों के समृद्ध सैन्य अनुभव के साथ शीर्ष पद पर पहुंचे हैं और 1997 के बाद से बख्तरबंद कोर से इस बल का नेतृत्व करने वाले पहले अधिकारी हैं।

MCQ

Q. हाल ही में भारतीय सेना के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?

A. जनरल मनोज पांडे

B. जनरल उपेंद्र द्विवेदी

C. जनरल धीरज सेठ

D. जनरल अनिल चौहान

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

ई-ओसीआई कार्ड

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में एफसीआरए 2.0 पोर्टल और बहुप्रतीक्षित ई-ओसीआई (इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड का शुभारंभ किया।

मुख्य बिन्दु:

ई-ओसीआई कार्ड

- इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ई-ओसीआई) कार्ड एक नागरिक-केंद्रित, कागज रहित दस्तावेज़ीकरण ढाँचा है, जिसे वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए डिज़ाइन किया गया है ।
- यह पारंपरिक, भौतिक ओसीआई स्टाम्प और पुस्तिका प्रारूप को एक संस्थागत, सुरक्षित रूप से सत्यापित डिजिटल क्रेडेंशियल में परिवर्तित करता है।
- **मंत्रालय:** गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार।

उद्देश्य:

- 50 लाख से अधिक ओसीआई धारकों के लिए भौतिक कागजी कार्रवाई, सत्यापन में देरी और प्रशासनिक लागत को समाप्त करना।
- भारत के सभी हवाई अड्डों पर वास्तविक समय की डिजिटल आव्रजन सुरक्षा लाइनों के साथ प्रवासी पहचान पत्रों को सीधे एकीकृत करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)

चर्चा में क्यों?

- गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन तय समय पर हो रहा है, और BNS, BNSS और BSS के तहत सभी जाँच और मुकदमे 1 जनवरी, 2027 से डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किए जाएंगे।

मुख्य बिन्दु:

अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)

- इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपराधिक न्याय वितरण नेटवर्क के मुख्य, पारंपरिक रूप से अलग-थलग पड़े स्तंभों को एक एकल संवादात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करता है।
- यह सरकार के मेघराज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किए गए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित डेटा फ्रेमवर्क के साथ पारंपरिक, कागजी कार्यप्रणालियों को प्रतिस्थापित करता है।
- **नोडल एजेंसी:** भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी)।
- **प्रौद्योगिकी भागीदार:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित और परिकल्पित।

MCQ

Q. अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है?

1. न्याय वितरण में पारदर्शिता
2. डेटा का त्वरित आदान-प्रदान
3. मामलों के शीघ्र निस्तारण में सहायता
4. विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय

सही उत्तर चुनिए—

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1, 3 और 4
D. 1, 2, 3 और 4

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

योजनाएँ एवं नीतियाँ

किसान सारथी प्लेटफ़ॉर्म

चर्चा में क्यों?

- किसान सारथी वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया भारत का सबसे बड़ा एकीकृत डिजिटल कृषि परामर्श मंच है।

मुख्य बिन्दु:

परिचय

- **प्रारंभकर्ता:** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- **कार्यान्वयन:** भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (IARI) तथा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा।
- यह मंच इंटरैक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली (IIDS) का उपयोग करता है। IIDS किसानों और विशेषज्ञों के बीच द्वि-दिशात्मक संवाद की सुविधा प्रदान करता है। यह कृषि ज्ञान के प्रयोगशाला से खेत तक हस्तांतरण को भी समर्थन देता है।

विशेषताएँ:

- किसान तथा उसके खेत की प्रोफ़ाइल के आधार पर व्यक्तिगत कृषि परामर्श प्रदान करता है।
- 13 क्षेत्रीय भाषाओं में विषय-विशेषज्ञों के साथ प्रत्यक्ष संवाद की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- किसानों की आवश्यकता के अनुसार कॉल एवं कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करता है।
- किसानों के ज्ञान डेटाबेस तक पहुँच उपलब्ध कराता है।

MCQ

Q. किसान सारथी प्लेटफ़ॉर्म का संयुक्त रूप से शुभारंभ किन मंत्रालयों द्वारा किया गया?

A. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय
B. इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
C. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय
D. नीति आयोग तथा कृषि मंत्रालय

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

सारस शक्ति

चर्चा में क्यों?

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन (आरजीवीएस) 2026 के दौरान सरस शक्ति संग्रह और सरस शक्ति कॉफी टेबल बुक लॉन्च की।

मुख्य बिन्दु:

सारस शक्ति

- यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख ब्रांडिंग और विपणन पहल है।

उद्देश्य:

- ब्रांडिंग, उत्पाद प्रचार और व्यापक बाजार संबंधों के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत करना।
- लखपति दीदियों और विकसित भारत की परिकल्पना का समर्थन करते हुए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के उत्पादों को उच्च स्तरीय संस्थागत और उपभोक्ता बाजारों में स्थापित करना।

MCQ

Q. सारस शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत एक ब्रांडिंग एवं विपणन पहल है।
2. इसका उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।
3. इसका संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

UTKARSH CIVIL SERVICES

विज्ञान प्रौद्योगिकी

डिजिटल इंडिया

चर्चा में क्यों?

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 1 जुलाई 2026 को अपने 11 वर्ष पूर्ण कर लिए।

मुख्य बिन्दु:

भारत का डिजिटल नेतृत्व

- पिछले एक दशक में डिजिटल इंडिया, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की आधारशिला बन चुका है।
- इसने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, स्टार्टअप विकास तथा प्रौद्योगिकी के अपनाने की गति को तेज किया है।
- भारत अब वैश्विक स्तर पर वास्तविक समय के डिजिटल भुगतानों में अग्रणी है, जहाँ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से विश्व के लगभग 49% रियल-टाइम डिजिटल लेन-देन संपन्न होते हैं।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12–14% योगदान है तथा अगले दशक में इसके लगभग एक-पाँचवाँ (20%) तक पहुँचने की अपेक्षा है।
- भारत ने वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडिया स्टैक ग्लोबल तथा वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार की शुरुआत की, जिससे भारतीय डिजिटल समाधानों की वैश्विक पहुँच का विस्तार हुआ।
- फरवरी 2026 तक भारत ने इंडिया स्टैक तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सहयोग डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान तथा सार्वजनिक सेवाओं के वितरण जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हैं।

डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ

- **ब्रॉडबैंड पहुँच:** विश्वसनीय ब्रॉडबैंड डिजिटल शासन तथा समावेशी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
- **मोबाइल कनेक्टिविटी की सार्वभौमिक पहुँच:** जनवरी 2026 तक भारतनेट-1 तथा भारतनेट-2 के अंतर्गत लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतों अर्थात् लगभग 97% ग्राम पंचायतों को लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।
- **सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम:** सुलभ डिजिटल सेवा केंद्र नागरिकों को उनके घरों के निकट ही डिजिटल सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराते हैं।
- **उदाहरण:** वर्तमान में 6.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres—CSCs) तथा 1.6 लाख डाकघर डिजिटल सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
- **ई-शासन:** यह कागजरहित, एकीकृत तथा नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देता है।
- डिजीलॉकर तथा राष्ट्रीय सिंगल साइन-ऑन जैसे मंच प्रमाण-पत्रों, आवेदनों, भुगतानों तथा सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे कागजी कार्यवाही कम होती है और जीवन-यापन की सुगमता बढ़ती है।
- **ई-क्रांति:** डिजिटल इंडिया के सेवा प्रदायगी स्तंभ के रूप में ई-क्रांति ने भौतिक से डिजिटल शासन की ओर संक्रमण को गति प्रदान की है।
- ई-हॉस्पिटल, ई-संजीवनी तथा ई-कोर्ट्स जैसे एकीकृत मंचों ने प्रमाण-पत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं तथा न्यायिक सेवाओं तक पहुँच को अधिक सरल बनाया है।
- **सभी के लिए सूचना:** यह स्तंभ सरकारी सूचनाओं को सरलता से उपलब्ध कराकर तथा डिजिटल मंचों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके पारदर्शी एवं सहभागी शासन को सुदृढ़ बनाता है।
- MyGov तथा ओपन गवर्नमेंट डेटा जैसी पहलें नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक सहज पहुँच प्रदान करती हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:** वित्त वर्ष 2014–15 में ₹1.9 लाख करोड़ के स्तर से बढ़कर मार्च, 2026 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग ₹12 लाख करोड़ तक पहुँच गया है।
- आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता है, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य शृंखला में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **रोज़गार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी:** भारत के 2,100 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र इंजीनियरिंग, विश्लेषिकी, साइबर सुरक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्षेत्रों में लगभग 26 लाख पेशेवरों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।
- **प्रारंभिक लाभ कार्यक्रम:** बायोमेट्रिक उपस्थिति, सुरक्षित सरकारी ई-मेल, सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट, ई-पुस्तकें, एसएमएस-आधारित मौसम चेतावनी तथा डिजिटल संचार मंच जैसी त्वरित प्रभाव वाली पहलों ने प्रौद्योगिकी-आधारित शासन के तत्काल लाभों को प्रदर्शित किया।

समावेशी दशक को गति देने वाली प्रमुख पहलें

जैम त्रिमूर्ति (JAM Trinity)

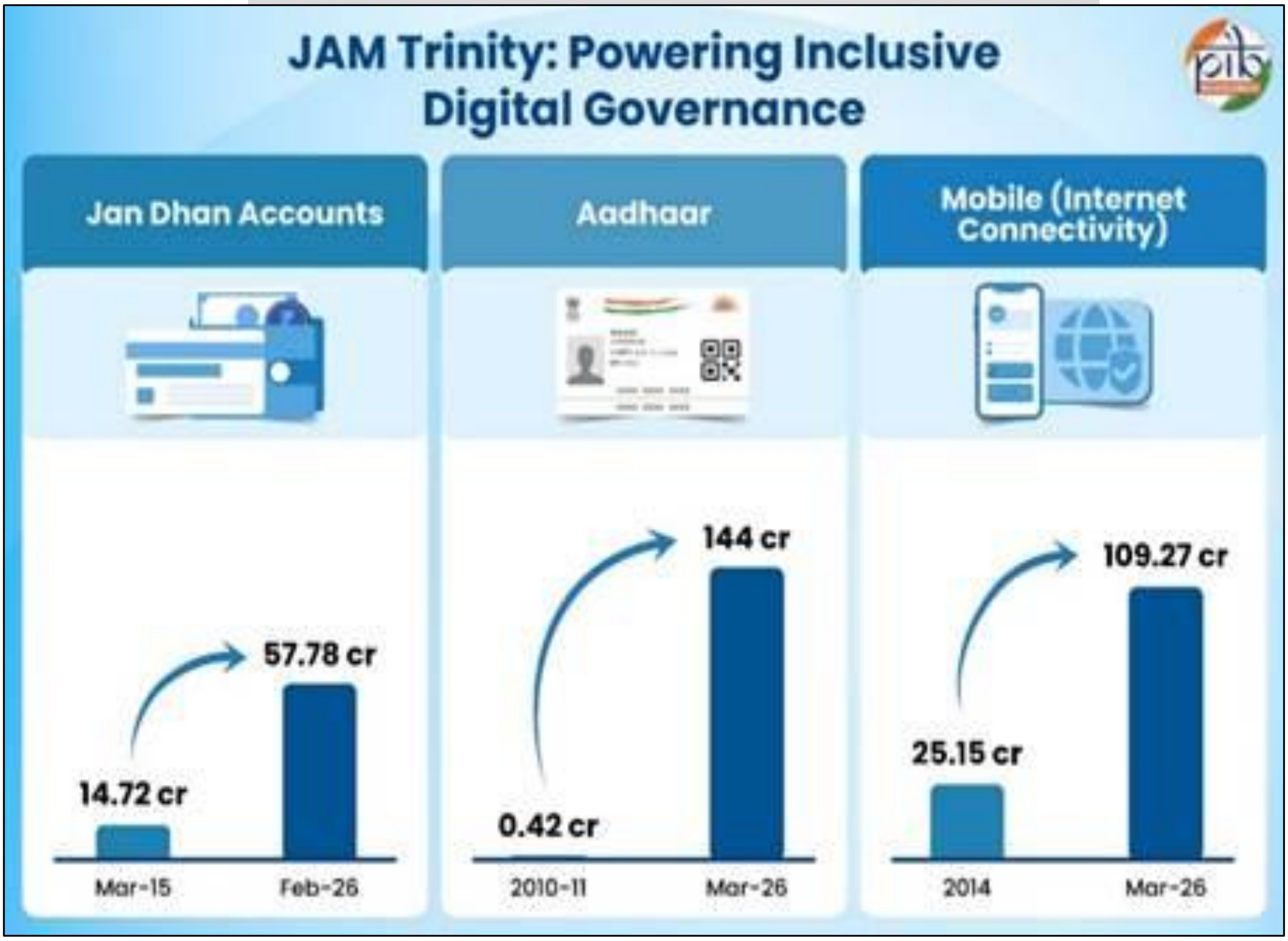

- डिजिलॉकर
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

सार्वजनिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने वाले डिजिटल मंच:

- ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ORS) रोगियों को डिजिटल माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **ई-संजीवनी:** यह टेलीमेडिसिन मंच विशेष रूप से ग्रामीण तथा वंचित क्षेत्रों में रोगियों को दूरस्थ रूप से डॉक्टरों से जोड़ रहा है।
- **टेली-मानस:** यह देशभर में नि:शुल्क टेली-परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराता है।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से वाणिज्य को सशक्त बनाना:

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सार्वजनिक खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष तथा कागजरहित बनाकर उसमें परिवर्तन किया है।
- डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क एक खुला एवं अंतरसंचालनीय डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है, जो विभिन्न मंचों पर खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ता है।
- **एग्रीस्टैक (AgriStack):** प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना
- **शिक्षा तक पहुँच को सशक्त बनाने वाले डिजिटल मंच:**
- दीक्षा (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing—DIKSHA) पाठ्यक्रम-आधारित डिजिटल शिक्षण सामग्री।
- स्वयं (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds—SWAYAM) तथा स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha) कक्षा से बाहर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का विस्तार कर रहे हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भारत की डिजिटल कार्यशक्ति को सशक्त बनाना:

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)
- फ्यूचरस्किल्स प्राइम (FutureSkills Prime)
- स्किल इंडिया डिजिटल हब (Skill India Digital Hub—SIDH)
- इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission)

RAS MAINS MODEL QUESTION:

Q. मान लीजिए कि आप किसी आकांक्षी जिले के जिलाधिकारी हैं जहाँ—

- इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है।
- डिजिटल साक्षरता कम है।
- अधिकांश सरकारी सेवाएँ ऑफलाइन संचालित हो रही हैं।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न स्तंभों का उपयोग करते हुए जिले में डिजिटल शासन को प्रभावी बनाने हेतु एक कार्ययोजना प्रस्तुत कीजिए।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- पर्यटन मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में "पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की ।

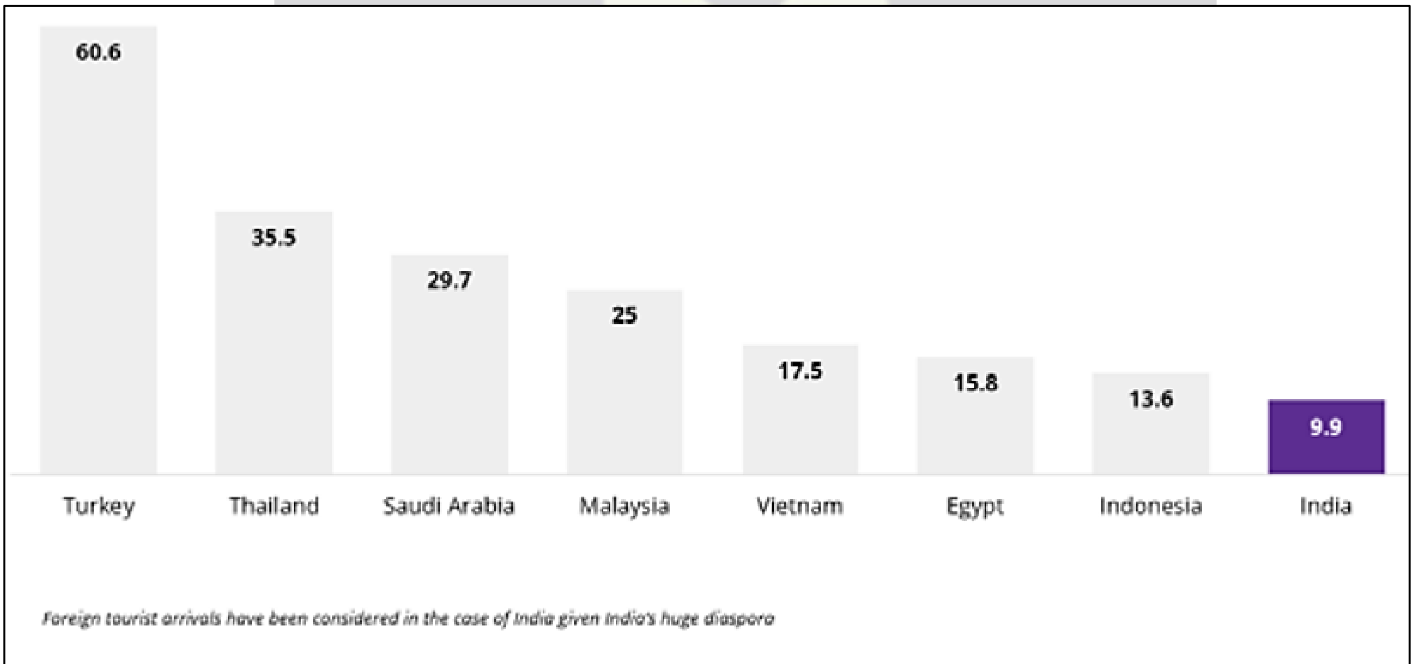

Figure 1.3: International Tourist Arrivals by Country (2024, Millions)

मुख्य बिन्दु:

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट

- यह रिपोर्ट भारत के पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नियामक बाधाओं का आकलन करती है। यह पर्यटन को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवास, आतिथ्य, परिवहन और यात्रा सेवाओं में सुधारों की सिफारिश करती है।

पर्यटन से संबंधित प्रमुख आँकड़े और सांख्यिकी:

- **घरेलू माँग में भारी उछाल:** भारत में 2024 में 2.9 अरब घरेलू पर्यटक आए, जो 2019 में महामारी से पहले के 2.3 अरब के उच्चतम स्तर को पार कर गया।
- **विदेशी पर्यटकों का आगमन:** भारत ने 2024 में 9.95 मिलियन विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया, जिससे पर्यटन राजस्व में लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता अंतर:** टीटीडीआई में भारत प्राकृतिक संसाधनों में 6वें और सांस्कृतिक संसाधनों में 9वें स्थान पर है, लेकिन समग्र रूप से केवल 39वें स्थान पर है।
- **परियोजनाओं में लंबी देरी:** भारत में होटल परियोजनाओं के लिए लगभग 60 स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है और इन्हें पूरा होने में 36-48 महीने लगते हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213